(ग) यदि हां, तो प्रत्येक विद्युत संयंत्र के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(घ) इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का वर्ष 1993-94 में हरियाणा को बिजली की आपूर्ति में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं। और हरियाणा की बिजली की कमी को पूरा करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (घ) मेगावाट में आहरित की गई बिजली की मात्रा क्षण-प्रतिक्षण भिन्न-भिन्न होती है और यह उपभोग की गई ऊर्जा को मिलियन यूनिट के संदर्भ में, एक समय में समेकित की जाती है। 1988-89 से 1992-93, (फरवरी, 1993 तक) हरियाणा का हिस्सा तथा उसके द्वारा वास्तविक रूप से आहरित की गई बिजली का ब्यौरा अनुपत्र में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 166, अनुपत्र संख्या 34)।

(ङ) तथा (च) उत्तरी क्षेत्र के केन्द्रीय क्षेत्र में 1993-94 के दौरान 848 मेगावाट की प्रत्याशित क्षमता अभिवृद्धि में से हरियाणा अपना देय हिस्सा प्राप्त करेगा। हरियाणा में बिजली की उपलब्धता अभिवृद्धि के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के विद्यमान विद्युत उत्पादन केन्द्रों से ईष्टतम विद्युत उत्पादन करना, नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वित करना, पारेषण तथा वितरण हानियों की मात्रा कम करना, प्रभावी भार प्रबन्धन तथा ऊर्जा संवर्धन, पड़ोसी राज्यों/प्रणालियों से सहायता प्रदान करना आदि।

Compensation to Tehri-Dam Oustees

1717. SHRI JAGDISH PRASAD MATHUR : Will the Minister of POWER be pleased to state the details regarding compensation paid by the Tehri Hydro Development Corporation to the tune of over Rs. 3 lakhs to the probable oustees of the proposed Tehri Dam falling under various categories such as Landless Labour, Agriculturists, Non-agriculturists-Grade-I, Non-agriculturists Grade-II and the Scheduled Caste ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF POWER (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU) : The compensation to the oustee families is being paid by Tehri Hydro Development Corporation as per the rehabilitation policy framed for urban and rural oustees. As per this policy 94 urban families are entitled to a compensation of more than Rs. 3 lakhs under urban rehabilitation programme. Under the rural rehabilitation programme, 20 rural families are entitled for cash compensation of more than Rs. 3 lakhs and 106 rural families are eligible for cash compensation of Rs. 1 lakh along with agricultural land whose cost is more than Rs. 2 lakhs. The compensation to the rural families is paid depending upon their entitlement, cost of land and other holdings etc.

Electrification of Villages in the Country

1718. SHRI DIGVIJAY SINGH :
SHRI MOHINDER SINGH LATHER :

Will the Minister of POWER be pleased to state :

(a) what is the number of villages electrified in the country during the year 1992, upto the 31st December, 1992, State-wise;

(b) whether there is any proposal under consideration of Government to electrify more villages during the current financial year;

(c) if so, the number of such villages, stating their details, State-wise;

(d) whether financial assistance was provided to each State for this purpose during the above period;

(e) whether Government have formulated any timebound scheme for the electrification of all the villages in the country; and